

रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण

बनाम

सुशील कुमार महतो और अन्य

21 जुलाई, 2006

(न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत और न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पांटा)

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-जनहित याचिका, बहुमंजिला इमारतों के निर्माण को अवैध मंजूरी देने का आरोप अस्वच्छ हाथों से आने वाले याचिकाकर्ता-हालांकि, प्राधिकरण को निर्देश उच्च न्यायालय द्वारा निगम द्वारा दी गई मंजूरी पर पुनर्विचार करने के लिए आयोजित की जाने वाली चुनौती: पर्याप्त सामग्री के बिना अधिकारियों की शिथिलता के बारे में निष्कर्ष निकाला गया था, इस प्रकार उनके खिलाफ जारी किए गए निर्देशों को हटा दिया जाना चाहिए, हालांकि, कोई भी अधिकारी लापरवाही पाए जाने पर-क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अधिनियम-भवन उपनियम, 1981 के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उत्तरदाता नं.1 ने जनहित याचिका दायर की जिसमें आरोप लगाया गया कि कुछ बहुमंजिला इमारतों के निर्माण को अवैध रूप से और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अधिनियम, भवन विनियम और भवन उपनियम, 1981 के प्रावधानों के विपरीत मंजूरी दी गई थी। उच्च न्यायालय ने पाया कि रिट याचिकाकर्ता और उसके समर्थकों ने निर्माण करते समय स्वीकृत योजनाओं का उल्लंघन किया था इमारतें और उनकी योजनाओं के लिए प्रतिबंध प्राप्त करते समय दिया गया वचन, लेकिन इसने अपीलकर्ता को निर्देश जारी किए-प्राधिकरण वर्तमान अपील द्वारा दी गई मंजूरी पर पुनर्विचार करने के लिए।

न्यायालय ने अपील का निपटारा करते हुए अभिनिर्धारित किया :

उच्च न्यायालय ने अधिकारियों की शिथिलता के बारे में पर्याप्त सामग्री के बिना निष्कर्ष निकाला यद्यपि कोलूसिका (*collusica*) के बारे में अथवा इस बारे में कोई निश्चित सामग्री नहीं थी कि वे भवन निर्माण उपनियमों के उल्लंघन पर आँख मूँद कर निष्क्रिय खड़े रहे और योजनाओं को मंजूरी दी . ये बहुत सामान्यीकृत दिशा-निर्देश थे। इसलिए, कार्रवाई शुरू करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को हटाया जाना होगा। हालाँकि, यदि यह अपीलकर्ता-प्राधिकरण के संज्ञान में आता है कि कोई अधिकारी जिसने वास्तव में प्राधिकरण के सर्वोत्तम हित के विपरीत कार्य किया हो तो उस के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही की जाए। 2002 में संशोधित उपविधि को उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मामले पर पुनः विचार करते समय ध्यान में रखा जायेगा परन्तु यदि यह पाया जाता है कि 2002 से पहले के नियमों का कोई उल्लंघन किया गया था, तो इसके आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। (780-बी-ई)

सिविल अपीलीय न्यायाधिकरण

सिविल अपील संख्या 3087/2006

(झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के निर्णय और आदेश दिनांक 30.09.2003 की सिविल अपील संख्या 1590/2002 डब्ल्यू.पी. में (पी.आई.एल.)

अपीलार्थियों के लिए पी.एस.मिश्रा, तथागत एच.वर्धन, उपेंद्र मिश्रा, ध्रुव कुमार झा, रवि सी. प्रकाश और सी.डी. सिंह।

प्रतिवादियों के लिए ए.एन. देव और एस. जननी

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत द्वारा सुनाया गया

अनुमति प्रदान की गई।

अपीलकर्ता जनहित याचिका (संक्षेप में 'पी.आई. एल.') के रूप में एक याचिका पर विचार करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा दिए गए कुछ निर्देशों की वैधता पर सवाल उठाता है।

याचिकाकर्ता ने कथित जनहित याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया कि कुछ बहुमंजिला इमारतों के निर्माण को अवैध रूप से और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अधिनियम (संक्षेप में 'अधिनियम') और भवन विनियमों (संक्षेप में 'विनियम') के प्रावधानों के विपरीत मंजूरी दी गई थी। और भवन उपनियम, 1981 (संक्षेप में 'उपनियम') अधिकारी और व्यक्ति जो बहुमंजिला इमारतों के निर्माता थे, पहले उपस्थित हुए। उच्च न्यायालय, और यह रुख अपनाया कि जनहित याचिका कुछ और नहीं बल्कि को बदनाम करने का एक शरारती प्रयास था, यह बताया गया कि याचिकाकर्ता इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि रिट याचिकाकर्ता और उसके कुछ समर्थकों ने स्वीकृत योजनाओं का उल्लंघन किया था। भवनों का निर्माण करते समय और उस समय दिए गए उपक्रम अपनी योजनाएं फिर भी के लिए मंजूरी प्राप्त करते हुए, उच्च न्यायालय ने पाया कि रिट याचिकाकर्ता पूरी तरह से पारदर्शी उद्देश्यों के साथ अदालत में नहीं आया होगा, लेकिन क्या निगम को मंजूरी के अनुसार उचित ठहराया गया था, इस पर उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार किया जाना था, उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि न केवल उस बिल्डर के मामले जिन्होंने रिट याचिका में खुद को शामिल किया था, बल्कि उन सभी जी के मामले भी जिन्होंने उप-कानूनों, स्वीकृत योजनाओं और उपक्रमों द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन किया है, इस आशय के निर्देश दिए गए थे कि यदि रिट याचिकाकर्ता या उसके समर्थकों ने उप-कानूनों का उल्लंघन किया है, तो उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा विरुद्ध अपीलकर्ताओं ने इन दिशानिर्देश हालांकि की शुद्धता पर सवाल नहीं उठाया है, कुछ मामलों के संबंध में शिकायत की जाती है। उन्हें इस मामले में सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया उनके पास है। नेकनियती से काम किया और इसलिए इन टिप्पणियों को हटा दिया जाना चाहिए।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि 2002 में उपनियमों में संशोधन किया गया है और जबकि पुनर्विचार किया जाना है, तो उन्हीं उपनियम के संदर्भ में होना चाहिए जो 2002 में लागू हुए हैं।

उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने इस स्थिति को स्वीकार किया कि 2002 हम में प्रस्तुत किए गए।

उपनियमों के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय द्वारा पर्याप्त सामग्री के बिना निष्कर्ष निकाला गया है कि अधिकारों की शिथिलता के बारे में कोई निश्चित सामग्री नहीं थी या कि वे भवन के उल्लंघन को निष्क्रिय रूप से खड़े थे-उपनियम और अनुमोदित योजनाओं ये बहुत सामान्यीकृत निर्देश दिये थे, इसलिए, हम शुरू करने के लिए उपरोक्त निर्देशों को सीधे हटाना, हालांकि, यह स्पष्ट करें कि यदि यह अपीलकर्ता प्राधिकरण के ध्यान में आता है कि कोई भी अधिकारी जिसने वास्तव में अधिकारियों के सर्वोत्तम हित के विपरीत काम किया था, उसके खिलाफ स्वीकृत स्थिति के दृष्टिकोण के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

अपीलकर्ता- प्राधिकरण के लिए यह पता लगाने के लिए गहन जांच करना अनिवार्य होगा कि क्या किसी भी मामले या मामलों में, संबंधित अधिकारियों ने की अवहेलना में काम किया है/किया है, जवाब सकारात्मक है, तो आवश्यक कार्रवाई का पालन करना होगा।

अपील का तदनुसार निपटान किया जाता है। कोई लागत नहीं।

एन. जे.

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।